

न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी, द्वारा मालिक कृष्णलाल ज्ञानवार

बनाम

यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य

23 अप्रैल, 2004

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जे.जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 20 - सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – क्षेत्राधिकार वाले एक से अधिक न्यायालय - एक समझौते के तहत पक्षों द्वारा एक न्यायालय तक क्षेत्राधिकार की सीमा – वैधता – अभिनिर्धारित: एक समझौते द्वारा पक्षकार क्षेत्राधिकार को किसी एक न्यायालय तक सीमित कर सकते हैं - हालाँकि, एक समझौते द्वारा पक्षकार उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते जिसके पास अन्यथा क्षेत्राधिकार नहीं है – संविदा अधिनियम, 1872

प्रत्यर्थी सं.1-वादी सं.1 ने वादी संख्या 2 को डिलीवरी के लिए बरनाला में कुछ सामान के परिवहन के लिए अपीलार्थी-प्रत्यर्थी को नियुक्त किया, जहां डिलीवरी से पहले आग के कारण सामन नष्ट हो गया था। प्रत्यर्थी नं.1 ने हर्जाने के लिए वादी नं.2 के साथ दावे का निपटारा किया, अपीलार्थी के खिलाफ न्यायालय में मुआवजे का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया गया जहां वाद-हेतुक उत्पन्न हुआ। अपीलार्थी ने यह तर्क दिया कि जिस न्यायालय में कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ, उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था क्योंकि प्रेषित माल नोट में विशेष रूप से उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का

संकेत दिया गया था जहाँ मुख्य कार्यालय स्थित था यानि उदयपुर और अन्य सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर रखा गया था।

विचारण न्यायालय ने तर्क को स्वीकार नहीं किया। अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को उलट दिया। उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल कर दिया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि प्रेषित माल के नोट में दर्शाए गए स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न्यायालय में मामले पर विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि पक्षकारों ने एक समझौते के द्वारा एक विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार तय कर दिया था और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया था।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. जहाँ सिविल प्रक्रिया संहिता क्षेत्राधिकार के तहत दो या दो से अधिक न्यायालयों के पास किसी वाद या कार्यवाही की सुनवाई करने का अधिकार है, वहां पक्षकारों के बीच एक समझौता होता है कि उनके बीच के विवाद की सुनवाई ऐसे किसी भी न्यायालय में की जाएगी, यह सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है और किसी भी तरह से संविदा अधिनियम 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए यदि किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर एक से अधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, तो पक्षकार अपनी सहमती से क्षेत्राधिकार को दो न्यायालयों में से

किसी एक तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन किसी समझौते के द्वारा पक्षकार किसी मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकते। विवादों का निपटारा करने के लिए दोनों पक्षों को दो सक्षम न्यायालयों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। एक बार जब पक्षकार खुद को इस तरह से बाध्य कर लेते हैं, तो उनके लिए एक अलग क्षेत्राधिकार चुनना खुला नहीं होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को अपास्त करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां चुने गए न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था।[629-ए-बी]

हाकम सिंह बनाम मैसर्स गैमन (इंडिया) लिमिटेड, एआईआर (1971) एससी 740 और मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम रामा मिश्रा, एआईआर (2002) एससी 2402, निर्भरता।

2. अन्य न्यायालयों के अपवर्जन के प्रश्न के संबंध में, पक्षकारों के इरादे को किसी विशेष न्यायालय के संदर्भ में "केवल", "अकेले", "अनन्य" और इसी तरह की अभिव्यक्तियों के उपयोग से समझा जा सकता है। लेकिन किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करने का इरादा स्पष्ट, असंदिग्ध, सुस्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे मामले में केवल अनुबंध की स्वीकृत धारणाएं ही पक्षों को बाध्य करेंगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि यह केवल उदयपुर का न्यायालय है जिसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। [629-जी]

पटेल रोडवेज लिमिटेड, बॉम्बे बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, [1991] 4 एससीसी 270, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2645/2004

सी.आर.सं.4602/2000 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17.2.2003 से।

शिव सागर तिवारी, यू.बी. चौरसिया, श्रीमती मणि मित्तल और प्रवीण पांडे, अपीलार्थियों की ओर से।

सुधीर के.गुप्ता, के.के.गुप्ता(एन.पी.) और एम.के.दुआ, प्रत्यर्थियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया –

अरिजीत पासायत, न्यायाधिपति

अवकाश अनुदत्त की गई।

इस अपील में, केवल एक ही सवाल उठाया गया है कि क्या उच्च न्यायालय का निष्कर्ष कि बरनाला के सिविल न्यायालय के पास प्रत्यर्थी संख्या 1-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (इसके बाद 'वादी संख्या 1' के रूप में संदर्भित) और और मालवा कॉटन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड (इसके बाद 'वादी संख्या 2' के रूप में संदर्भित) द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार था, जबकि विचारण न्यायालय ने माना कि बरनाला न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अन्यथा

निर्धारित किया। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में 'सीपीसी') की धारा 115 के तहत दायर पुनरीक्षण को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा निर्धारित किया कि विचारण न्यायालय का दृष्टिकोण सही था।

विवाद निम्नलिखित पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ।

वादी नंबर 2 ने कुछ वस्तुएं खरीदी थीं जो 29 गांठों में बुक थीं। बरनाला तक परिवहन के लिए सामग्री को न्यू मोगा ट्रांसपोर्ट कंपनी, वर्तमान अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) के पास बुक किया गया था। माल ट्रक नंबर HYN 6973 में लोड किया गया था। प्रेषित माल 23.5.1993 को सुबह 9.30 बजे वादी नंबर 2 की फैक्ट्री के पास बरनाला पहुंचा। कथित तौर पर बिजली के शॉर्ट-सर्किट के कारण लगी आग से सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। वादी नंबर 2 ने दावा किया कि उसे नुकसान हुआ है और वर्तमान अपीलकर्ता यानी प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ रुपये 510000 की राशि के लिए दावा दायर किया। चूँकि कुछ भी भुगतान नहीं किया गया था और अपीलकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) द्वारा केवल माल की गैर-प्रदत्त प्रमाणपत्र जारी किया गया था, प्रतिवादी नंबर 1 (वादी नंबर 1) ने रुपये की राशि के लिए दावे का निपटारा किया। सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर 463516 रुपये का भुगतान वादी संख्या 2 को किया गया और उचित रसीद प्राप्त की गई। वादी नंबर 2 ने राशि प्राप्त होने पर वादी नंबर 1 के पक्ष में सभी अधिकारों को सौंपने, त्यागने और स्थानांतरित करने के लिए प्रतिस्थापन-सह-विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी का एक पत्र निष्पादित किया, जो प्रतिवादी नंबर 1, वर्तमान अपीलकर्ता से मुआवजे का दावा करता है। मुकदमे में अन्य बातों के

साथ-साथ वर्तमान अपीलकर्ता द्वारा एक विशिष्ट तर्क दिया गया था कि बरनाला न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। प्रेषित माल नोट के संदर्भ में, यह प्रस्तुत किया गया कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार केवल उदयपुर न्यायालय के पास है। प्रेषित माल नोट में यह दर्शाया गया था कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार उदयपुर में स्थित है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि केवल उदयपुर की न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। लेकिन अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। आक्षेपित फैसले के द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को बहाल कर दिया और माना कि वादी राहत के हकदार थे और बरनाला न्यायालय का क्षेत्राधिकार था।

अपील के समर्थन में, अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से अनदेखा कर दिया है कि पक्षकारों ने एक समझौते द्वारा एक विशेष न्यायालय को वह न्यायालय निर्धारित किया है जिसे मुकदमे का विचारण करने का क्षेत्राधिकार है। बिना किसी प्रशंसनीय कारण या आधार के उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को विक्षिप्त कर दिया।

निर्विवाद रूप से, प्रेषित माल के नोट में यह इस प्रकार कहा गया था:

"परिवहन के लिए सौंपे गए माल पर खेप के तहत उत्पन्न होने वाले सभी दावों और मामलों के संबंध में प्रधान कार्यालय शहर का न्यायालय ही क्षेत्राधिकार होगा।"

इसके अतिरिक्त, प्रेषित माल के नोट के शीर्ष पर क्षेत्राधिकार उदयपुर न्यायालय के पास निर्दिष्ट किया गया है। प्रेषित माल के नोट में उपरोक्त संकेत के संदर्भ में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि चुने गए न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों का स्पष्ट बहिष्कार है और इसलिए, वाद पर किसी अन्य स्थान पर विचार नहीं किया जा सकता था। दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने अपने उचित परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक स्थिति की सराहना नहीं की और कहा कि बरनाला के न्यायालय को सामान्य रूप से क्षेत्राधिकार मिला होगा। प्रेषित माल के नोट में सन्निहित बहिष्करण खंड और प्रेषित माल नोट में विशिष्ट संकेत के कारण कि अकेले उदयपुर न्यायालय के पास क्षेत्राधिकार है, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था।

प्रत्यर्थी संख्या I (वादी नंबर 1) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रेषित माल नोट स्पष्ट नहीं था और प्रेषित माल नोट में जो कहा गया था, वह यह था कि "सभी दावों के संबंध में मुख्य कार्यालय शहर का न्यायालय ही क्षेत्राधिकार होगा और परिवहन के लिए सौंपे गए माल की खेप के तहत उत्पन्न होने वाले मामले"। हालाँकि दोनों पक्ष समझौते से क्षेत्राधिकार को उस न्यायालय तक सीमित कर सकते हैं जिसके पास अन्य न्यायालयों के साथ क्षेत्राधिकार था, फिर भी क्षेत्राधिकार से संबंधित न्यायालय के अस्पष्ट संकेत को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने उचित रूप से हस्तक्षेप

किया है। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसी तकनीकी दलीलों के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने में काफी देरी हुई है और विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि बरनाला के न्यायालय का क्षेत्राधिकार था। मुकदमे के उद्देश्य को विफल करने के लिए प्रतिवादी नंबर I (यहाँ अपीलकर्ता) द्वारा एक बहुत ही तकनीकी तर्क दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रेषित माल के नोट में प्रधान कार्यालय को संदर्भित किया गया है, बिना यह बताए कि प्रधान कार्यालय कहां है। अस्पष्ट संकेत को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि पक्षकारों ने समझौते से किसी एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया है। इसलिए, यह जानना संभव नहीं है कि क्या प्रेषित माल के नोट में खंड 16 में उल्लिखित न्यायालय क्षेत्राधिकार वाले किसी विशेष न्यायालय को संदर्भित करता है या क्षेत्राधिकार से असंबद्ध था।

इसी तरह के सवाल की इस अदालत द्वारा कई मौकों पर जांच की गई है।

सीपीसी की धारा 20 इस प्रकार है:

"20. अन्य वाद वहां संस्थित किये जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद-हेतुक पैदा होता है- पूर्वोक्त परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, हर वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

(1) प्रतिवादी, या जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां प्रतिवादियों में से हर एक वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में

और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है; अथवा

- (2) जहाँ एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहाँ प्रतिवादियों में से कोई भी प्रतिवादी वाद के प्रारंभ के समय वास्तव में और स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परन्तु यह तब जबकि ऐसी अवस्था में या तो न्यायालय की इजाजत दे दी गई है या जो प्रतिवादी पूर्वोक्त रूप में निवास नहीं करते या कारबार नहीं करते या अभिलाभ के लिए स्वयं काम नहीं करते, वे ऐसे संस्थित किए जाने के लिए उपगत हो गए हैं; अथवा

- (3) वाद-हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है।

(स्पष्टीकरण)- निगम के बारे में यह समझा जाएगा के वह भारत में के अपने एकमात्र या प्रधान कार्यालय में या किसी ऐसे वाद-हेतुक की बाबत, जो ऐसे किसी स्थान में पैदा हुआ है जहाँ उसका अधीनस्थ कार्यालय भी है, ऐसे स्थान में कारबार करता है।”

आम तौर पर, खंड (ए) से (सी) के तहत वादी के पास मंच का विकल्प होता है और उसे प्रतिवादी के निवास स्थान या व्यवसाय पर जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और वह उस स्थान पर मुकदमा दायर कर सकता है जहां कार्रवाई का

कारण उत्पन्न होता है। यदि प्रतिवादी किसी स्थान पर केवल इसलिए मुकदमेबाजी में घसीटे जाने से बचना चाहता है क्योंकि वहां कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है तो वह बहिष्करण खंड द्वारा ऐसी स्थिति से खुद को बचा सकता है। हालाँकि, स्पष्टीकरण का स्पष्ट आशय यह है कि जहाँ निगम के पास उस स्थान पर एक अधीनस्थ कार्यालय है जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है, यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वहाँ उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वह उस स्थान पर व्यवसाय नहीं करता है। धारा 20 के खंड (ए) और (बी) अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय सीमा के भीतर एक न्यायालय को संदर्भित करते हैं जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी अन्य बातों के साथ-साथ "व्यवसाय करता है"। दूसरी ओर खंड (सी) उस न्यायालय को संदर्भित करता है जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर कार्रवाई का कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है।

धारा 20 सीपीसी के स्पष्टीकरण के सामान्य रूप से पठन से यह स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण में दो भाग होते हैं, (i) "भारत में कार्यालय" शब्दों और "के संबंध में" शब्दों के बीच आने वाले "या" शब्द से पहले और उसके बाद अन्य। स्पष्टीकरण प्रतिवादी पर लागू होता है जो एक निगम है जिसके शब्द में एक कंपनी भी शामिल होगी। स्पष्टीकरण का पहला भाग केवल ऐसे निगम पर लागू होता है जिसका एकमात्र या प्रधान कार्यालय किसी विशेष स्थान पर है। उस स्थिति में, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कंपनी का एकमात्र या प्रधान कार्यालय स्थित है, उसके पास भी क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि भले ही प्रतिवादी वास्तव में उस स्थान पर व्यवसाय नहीं

कर रहा हो, लेकिन स्पष्टीकरण द्वारा बनाई गई कल्पना के कारण उसे उस स्थान पर व्यवसाय करना माना जाएगा। स्पष्टीकरण के उत्तरार्द्ध भान में ऐसे मामले का ध्यान रखा जाता है जिसमें प्रतिवादी का एकमात्र कार्यालय नहीं है, लेकिन एक स्थान पर उसका प्रधान कार्यालय होता है और दूसरे स्थान पर उसका अधीनस्थ कार्यालय भी होता है। स्पष्टीकरण में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "ऐसे स्थान पर" और शब्द "या" जो विच्छेदनात्मक है, स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि यदि मामला स्पष्टीकरण के उत्तरार्द्ध के अंतर्गत आता है, तो यह वह न्यायालय नहीं है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रतिवादी का प्रधान कार्यालय स्थित है, बल्कि वह न्यायालय है जिसके क्षेत्राधिकार में इसका एक अधीनस्थ कार्यालय है जिसके पास अकेले ही "किसी भी स्थान पर उत्पन्न होने वाली कार्रवाई जहां इसका अधीनस्थ कार्यालय भी है" अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।

1976 में सीपीसी में संशोधन से पहले धारा 20 में दो स्पष्टीकरण थे, स्पष्टीकरण I और II। संशोधन अधिनियम द्वारा, स्पष्टीकरण I को हटा दिया गया और स्पष्टीकरण II को वर्तमान स्पष्टीकरण के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। जिस स्पष्टीकरण को हटा दिया गया था, वह इस प्रकार है:

स्पष्टीकरण 1. – जहां किसी व्यक्ति का एक स्थान पर स्थायी निवास है और दूसरे स्थान पर अस्थायी निवास भी है, तो उसे उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी कारण के संबंध में दोनों स्थानों पर निवास करने वाला माना जाएगा जहां उसका ऐसा अस्थायी निवास है।

यह स्पष्टीकरण प्रतिवादी के निवास स्थान के मामले से सम्बंधित है और ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसका एक स्थान पर स्थायी निवास है और दूसरे स्थान पर अस्थायी भी है, ऐसे व्यक्ति को उस स्थान पर उत्पन्न होने वाले किसी भी कारण के संबंध में जहां उसका ऐसा अस्थायी निवास है, दोनों स्थानों पर निवास करने वाला माना जाएगा। दूसरी ओर स्पष्टीकरण II में प्रयुक्त भाषा, जो वर्तमान स्पष्टीकरण है, पूरी तरह से अलग थी। यदि इरादा यह था कि यदि किसी निगम का प्रधान कार्यालय एक स्थान पर और अधीनस्थ कार्यालय दूसरे स्थान पर है और कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होता है जहां उसका अधीनस्थ कार्यालय है, तो यह माना जाएगा कि वह दोनों स्थानों पर व्यवसाय कर रहा है, स्पष्टीकरण-II में प्रयुक्त भाषा स्पष्टीकरण-I के समान होगी जो एक व्यक्ति के एक स्थान पर स्थायी निवास और दूसरे स्थान पर अस्थायी निवास के मामले से निपट रही थी।

उपरोक्त स्थिति पटेल रोडवेज लिमिटेड, बॉम्बे बनाम प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, [1991] 4 एससीसी 270 में इंगित की गई थी।

निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां सीपीसी क्षेत्राधिकार के तहत दो या अधिक न्यायालयों को किसी मुकदमे या कार्यवाही की सुनवाई करनी होती है, तो पक्षकारों के बीच एक समझौता होता है कि उनके बीच के विवाद की सुनवाई ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में की जाएगी, यह सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है और किसी भी तरह से भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है। इसलिए, यदि किसी दिए गए मामले के तथ्यों पर

एक से अधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, तो पक्षकार अपनी सहमति से क्षेत्राधिकार को दो न्यायालयों में से किसी एक तक सीमित कर सकते हैं। लेकिन किसी समझौते के द्वारा पक्ष किसी ऐसे न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं दे सकते जिसके पास अन्यथा किसी मामले से निपटने का क्षेत्राधिकार नहीं है। (देखें: हाकम सिंह बनाम मैसर्स गैमन (इंडिया) लिमिटेड, एआईआर (1971) एससी 740 और मेसर्स श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम रामा मिश्रा, एआईआर (2002) एससी 2402।

उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में मामले के मौजूदा तथ्यों पर गौर करना होगा।

यदि यह केवल प्रेषित माल के नोट में इंगित किया गया था तो प्रधान कार्यालय शहर के न्यायालय का क्षेत्राधिकार था, तो उस स्थान के सटीक संकेत के अभाव में इसका परिणाम क्या होगा, हम वर्तमान में चिंतित नहीं हैं, विशेष रूप से, जब प्रेषित माल के नोट में ही संकेत दिया था कि केवल उदयपुर न्यायालय का क्षेत्राधिकार था।

जैसा कि इस न्यायालय ने श्रीराम के मामले (सुप्रा) में हाकम सिंह के मामले (सुप्रा) का जिक्र करते हुए देखा था, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रभावित करने वाला कोई समझौता अमान्य नहीं है। विवादों का निपटारा करने के लिए दोनों पक्षों को दो सक्षम न्यायालयों में से किसी एक को चुनने का अधिकार है। एक बार जब पक्षकार खुद को इस तरह से बाध्य कर लेते हैं, तो उनके लिए एक अलग क्षेत्राधिकार चुनना खुला नहीं होता है।

तथ्यात्मक और कानूनी स्थिति से ऊपर, अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को रद्द करना उच्च न्यायालय के लिए उचित नहीं था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां चुने गए न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए, एकमात्र प्रश्न अन्य न्यायालयों को बाहर करने से संबंधित है।

पक्षकारों के इरादे को किसी विशेष न्यायालय के संदर्भ में "केवल", "अकेले", "अनन्य" और इसी तरह की अभिव्यक्तियों के उपयोग से समझा जा सकता है। लेकिन किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर करने का इरादा स्पष्ट, असंदिग्ध, सुस्पष्ट और विशिष्ट शब्दों में परिलक्षित होना चाहिए। ऐसे मामले में केवल अनुबंध की स्वीकृत धारणाएं ही पक्षों को बाध्य करेंगी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि यह केवल उदयपुर का न्यायालय है जिसके पास मुकदमे की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त करते हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को बहाल करते हैं। बरनाला न्यायालय अपनी मुहर के तहत उचित समर्थन के साथ वाद को वादी संख्या I (प्रतिवादी संख्या I) को वापस कर देगी, जो इसे उदयपुर में उचित न्यायालय के समक्ष इस तरह के समर्थन की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पेश करेगी। यदि ऐसा किया जाता है, तो परिसीमा का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और मामले का निर्णय कानून के अनुसार उसके गुणों के आधार पर किया जाएगा। अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक अधिवक्ता विनायक कुमार जोशी की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।
